inter-alia violation of the provisions of Sections 159, 209, 120, 211, 220, 224, 225, 229 and 301 of the Companies Act, 1956 and a copy of the investigation report has been forwarded to the Regional Director, Calcutta, for further necessary action in the matter.

Scheme to attract NRI investment in real estate

580. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the scheme to attract NRI investigation in real estate covering housing and commercial constrtuction is pending with his Ministry for clearance;

(b) if so, since when it is pending with his Ministry;

(c) the reasons for which it is pending and whether Government propose to clear it; and

(d) if so, by when ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARMANGALAM) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

लोक अदालतों का कार्यकरण

581. **श्री राघव जी** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से गत तीन वर्षों से किन-किन राज्यों में लोक अदालतों के प्रयोग चल रहे हैं;

(ख) उक्त तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने-कितने मामलों का निराकरण किया गया; और

(ग) क्या सरकार की कोई ऐसी पद्धति अपनाने की योजना है जिससे छोटे-छोटे मामलों का निपटारा शीघ्रता से हो सके ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) कलैंडर वर्ष, 1989 के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्णाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पांडिचेरी में लोक अदालतें आयोजित की गई हैं।

(ख) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	निपटाए गए मामलों की संख्या
1989	4,12,455
1990	6,42,462
1991	1,32,255

(ग) लोक अदालत, जो समझा-बुझाकर और सुलह के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए स्वैच्छिक प्रयास है, न्यायालय के बाहर मामलों के शीघ्र निपटारे का प्रभावी तंत्र साबित हुई है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों का भरा जाना

582. **श्री राघव जी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं उसकी खंडपीठों में न्यायाधीशों के कुल कितने पद रिक्त हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन पदों को भरने के लिए अपनी अनुशंसा भेज दी है, यदि हां तो इन्हें कब भेजा गया तथा उन पर कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने में होने वाले विलम्ब के कारण क्या हैं तथा इन्हें कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): (क) 30-4-92 को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के 4 पद और अपर न्यायाधीशों के 4 पद रिक्त थे।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों के रिक्त पद भरे जाने के संबंध में, मुख्य न्यायमूर्ति और मध्य प्रदेश के प्राधिकारियों से 29-1-92 को सिफारिशें प्राप्त हुई थीं। इन सिफारिशों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कार्यवाही की गई है। तथापि, यह बताना संभव नहीं है कि कब तक इस विषय में अंतिम विनिश्च हो जाएगा।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में दस वर्षों से अधिक अवधि से लंबित मामले

583. **श्री राघव जी** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** 9 मार्च, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 1676 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय तथा देश के उच्च न्यायालयों में ऐसे कितने मामले हैं जो पिछले दस वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : उच्च न्यायालयों की बाबत जानकारी संलग्न विवरण में प्रस्तुत है। (नीचे देखिए) जहां तक उच्चतम न्यायालय का संबंध है, जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या

क्रम सं०	उच्च न्यायालय का नाम	10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामले	निम्नलिखित तारीख को
1	इलाहाबाद	42674	31-12-90
2	आन्ध्र प्रदेश	125	31-12-90
3	मुंबई	10383	30-06-91
4	कलकत्ता	31165	31-12-90
5	दिल्ली	13606	31-12-91
6	गुवाहाटी	139	30-06-91
7	गुजरात	4216	30-06-91
8	हिमाचल प्रदेश	728	30-06-90
9	जम्मू-कश्मीर	1178	31-12-90
10	कर्नाटक	439	30-06-91